प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं ग्रामीण युवा

शशि कुमार सैनी
रामनगर, रूड़की।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत में विश्व कौशल युवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा ''मेक–इन–इंडिया'' कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए शुरू की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को कौशल के प्रति योग्यता प्रदान करने के साथ उनमें कार्य को पूरा करने की दक्षता को बढ़ाना है। यह योजना केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखारकर उनकी योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना से अधिक से अधिक लोग जोड़ने के लिए सरकार ने कई टेलीकॉम कम्पनियों को अपने साथ जोड़ा है। यह मोबाईल कम्पनियां मैसेज के द्वारा इस योजना को सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मन्त्रालय की ओर से संचालित की जा रही हैं। इस योजना के द्वारा देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसके प्रशिक्षण की फीस भी सरकार स्वयं ही वहन करती है। इस योजना के अन्तर्गत कम पढ़े–लिखे या दसवीं, बारहवीं उत्तीर्ण या बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने वर्ष 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2022 तक 40 करोड़ भारतीय युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित करना है।

सफलता जादू से नहीं मिलती है, सफल होने के लिये कौशल विकास की आवश्यकता होती है। युवा ऊर्जा किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने वाली ताकत हो सकती है बशर्ते उसे प्रभावी ढंग से सही दिशा दी जाये। कौशल विकास और रोजगार बुनियादी ताकत को बढ़ाने के लिये अच्छे साधन हैं, युवा जनसंख्या के मामले में भारत के पास सबसे बड़ा भण्डार है फिर भी भारतीय नियोक्ता कुशल मानव बल की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है। श्रम ब्यूरो की वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुशल कार्य बल केवल 2 प्रतिशत है। इसके अलावा पारम्परिक शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के बड़े वर्ग की रोजगार सम्बन्धी योग्यता की एक बड़ी चुनौती है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था शानदार मस्तिष्कों को जन्म तो दे रही है, परन्तु रोजगार के लिये विशेष कौशल की कमी है।

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना आसानी से सूक्ष्म उपायों के निर्माण के लिये स्वयं संसाधन उपलब्ध कराती है जैसे दरजी, हाथ कढ़ाई के कार्य, पोल्ट्री फार्म, ई. रिक्शा, बढ़ई आदि लघु उद्योगों का निर्माण इसी योजना का परिणाम है। आज देश की पारम्परिक कला और शिल्प की विरासत के संरक्षण के लिये नई पीढ़ी के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों का निर्माण करना एक कठिन कार्य है हालांकि चिकनकारी, हस्त निर्मित खेल के सामान आदि जैसे व्यवसायों को इस योजना में पहले ही चुना जा चुका है। इस योजना का लक्ष्य भारत में तकनीकी शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाकर उसे विश्व की मांग के अनुरूप ढालना है। मा. प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि भारत परम्परागत शिक्षा पाठयक्रम प्रचलन में विश्व में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ अपने आपको गतिशील नहीं बना पाया और यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या तेजी से बड़ रही है। इसके लिये यह आवश्यक है कि हम अपने शैक्षिक पाठयक्रमों में विश्व की मांग के अनुसार बदलाव लायें। आने वाले दशकों में किस तरह के कौशल की मांग सबसे अधिक होगी उसका अध्ययन करके अपने देश में उस अध्ययन से निष्कर्ष के आधार पर हम भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे तो भारत के युवाओं को रोजगार के सबसे अधिक अवसर प्राप्त होंगे इस तरह

कौशल भारत–कुशल भारत एक आंदोलन है न कि सिर्फ एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को पूरा करने वाले युवाओं को मंत्रालय द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो सभी सरकारी व निजी क्षेत्रों के साथ–साथ विदेशी संगठनों, संस्थाओं एवं उद्यमों में भी वैध माना गया है। इस योजना में गांव के वह युवा जो हस्त शिल्प, कृषि, बागबानी के कार्यों में परम्परागत हुनर रखते हैं, उनकी आय को अधिक करने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। कौशल भारत कुशल भारत सम्पूर्ण राष्ट्र का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में मैं भारत को विश्व कौशल की राजधानी बनाने के लिये पूरे राष्ट्र को प्रतिज्ञा करने का आह्वान करता हूं और कौशल विकास योजना केवल जेब में रूपये भरने जैसी संस्था नहीं है। भारत में 65 प्रतिशत युवा 35 वर्ष से कम आयु के हैं, जो रोजगार के अवसर की तलाश में देश से विदेशों में पलायन कर रहे हैं। यदि उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षित कर मांग के अनुसार तैयार कर दिया जाये तो भारतीय युवा वर्ग का भविष्य संवर सकता है। आज हमारा देश बहुत अधिक संख्या में डाक्टर, इन्जीनियर को तैयार करता है, और दुनिया के विकसित देशों को उनकी जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जी ने यह कौशल विकास योजना शुरू की है ताकि हम अपने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकें। कौशल विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी कठिनाईयां हैं हमारी साक्षरता दर आज भी अपेक्षा से कम है हमारे यहां विश्व स्तरीय व्यवस्था उच्च शिक्षा में नहीं है। शिक्षा का बुनियादी ढांचा कमजोर है, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी है। ऐसी स्थिति में कौशल भारत कार्यक्रम को पूर्ण करने में थोड़ा समय लग सकता है। कौशल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को इस दिशा में जिला स्तर पर शिक्षित बेरोजगारों और अशिक्षितों के लिये प्रशिक्षण केंद्र एवं कार्यशालाओं के आयोजन के प्रयास करने होंगे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना में कृषि, गृह सज्जा, सौन्दर्य और कल्याण, मोटर वाहन, निर्माण कार्य, इलैक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, रत्न एवं ज्वैलरी, हस्तशिल्प, चमड़ा पाईप लाईन, बिजली उद्योग, रबड़, खेल, दूरसंचार, वस्त्र और हस्तकला जैसे अन्य विभिन्न तरीकों के 34 कोर्सो के प्रशिक्षणों को शामिल किया गया है। इस योजना में सरकार ने प्रारम्भ में 15,000 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें लगभग 220 करोड़ रूपये उन युवाओं पर खर्च किया जा रहा है, जो पहले से ही विशेष प्रशिक्षण ले चुके हैं और लगभग 67 करोड़ रूपये इस योजना को संचालित करने एवं युवाओं को जागरूक करने के लिए किया जायेगा और लगभग 67 करोड़ रूपये सरकार मेंटरशिप और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए करेगी, ताकि बेरोजगार युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जा सके। सरकार का प्रयास है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सहायता से युवाओं को सशक्त और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भारतीय युवाओं को परिणाम के आधार पर कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिये सक्षम बनाना है क्योंकि कई बेरोजगार युवक पैसे की कमी की वजह से अपना मन–पसन्द प्रशिक्षण नहीं कर पाते है। इस वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। हालांकि देश में कई निजी प्रशिक्षण केन्द्र हैं, परन्तु उनका शुल्क इतना अधिक होता है कि गरीब युवाओं के लिए धन के अभाव में वहां प्रशिक्षण प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रशिक्षण योजना के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं रखा है। बल्कि सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर पुरस्कार के रूप में 8000/– रूपये का रिवार्ड भी दिया जाता हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत छोटे–बड़े आवश्यक और कई कारगर कोर्सो को शामिल किया गया है, जिनकी समयावधि भी 03 माह से 06 माह रखी गयी है। और कुछ कठिन कोर्सों के लिए अधिकतम 01 वर्ष का भी समय निर्धारित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जिन युवाओं ने अपना नामांकन कराया है, उन्हें अपना कौशल विकास का प्रदर्शन करना अनिवार्य है। यदि युवा किसी भी तरह से स्वयं को कोर्स के अनुरूप योग्य नहीं बना पाते हैं या

अपने कौशल का सही रूप से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कौशल विकास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। इस योजना में प्रशिक्षणार्थी के ऊपर जो भी खर्चा आयेगा उसे सरकार स्वयं वहन करती है और वह पैसा ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग सेन्टर के अकाउन्ट में भेज दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद छः माह में कौशल विकास मेलों का आयोजन भी किया जाता है जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया जाता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य सिर्फ युवाओं को सशक्त करने के लिए सिर्फ प्रशिक्षण देना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके बाद उन्हें रोजगार मुहैया कराना भी एक अहम काम है ताकि प्रशिक्षण के दौरान जो भी उन्होंने सीखा है, उसका प्रयोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कर सके।

भारत सरकार ने कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाले सभी युवाओं के लिए दो महत्वपूर्ण सुवधिाएं भी देने की घोषण की हैं, जिसमें कौशल भारत के अन्तर्गत उन सभी उम्मीदवारों को दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है जिसमें किसी भी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो जाने पर 02 लाख रू. तक की कुल बीमा धनराशि 03 वर्षों तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना का लक्ष्य केवल देश के युवाओं को रोजगार दिलाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के दम पर रोजगार दिलाना है। इस योजना में 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक आय समूह में है, जो कि भारत को एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। परन्तु एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का लाभ तभी मिलेगा जब हमारी जनसंख्या खासकर युवा वर्ग स्वस्थ, शिक्षित और कुशल होगा। भारत के पास एक अतुलनीय युवा जनसंख्या है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक, आर्थिक विकास को जोरदार बढ़ावा मिलना निश्चित है। हमारे पास लगभग 61 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से न केवल रोजगार के स्रोत बढ़ेंगे, बल्कि युवा वर्ग अपने जीवन को काबिल बनाने के साथ–साथ दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे। इस योजना को कौशल विकास और उद्यम मन्त्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें शुरूआत में 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया गया है। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय लागू किये गये प्रमुख कार्यक्रम मेक–इन–इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की मांगों को भी ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 2300 केन्द्रों के एन.एस.डी.सी. के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकारों से सम्बन्धित अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को भी इस योजना के प्रशिक्षण के लिए जोड़ा गया है। इस दिशा में उठाये गये सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नई राष्ट्रीय कौशल निधि तैयार की गयी है, जिसके जरिए सन् 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कौशल विकास योजना का प्रयास एक मिशन के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत तीन संस्थाएं कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कौशल विकास के प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है। एन.एस.डी.सी. एक गैर लाभ कम्पनी है जो गैर संगठित क्षेत्र में श्रम बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा कर रही है। आज भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थ व्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है। और भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में शामिल हो

जायेगा। वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र भी बन जायेगा। भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अवश्य ही हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। नई नीति के अन्तर्गत मिशन के तौर पर लागू की गयी यह योजना मानव संसाधन और उद्योग के विकास में एक नये युग की शुरूआत करेगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अधिकतर लाभ शहरी नागरिकों के द्वारा उठाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं तक यह योजना पहुंचने में कठिनाई हो रही है। सरकार का यह प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी इस योजना से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक कौशल विकास के केन्द्रों की स्थापना की जाये ताकि सभी बेरोजगार युवा कौशल विकास योजना से लाभान्वित हो सकें।